

42 A / 2018

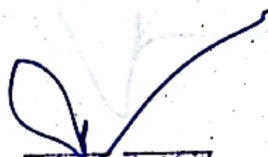
तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियल्य जज

11/8/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी को अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। प्रार्थीनी अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया कि विप्रार्थी पक्ष लम्बे समय से जवाब पेश नहीं कर रहे हैं, जो जवाब बन्द कर बहस सुनी जावे। विप्रार्थी को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अपलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीनी/वादीनी माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनते हैं। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

  
राजस्थान कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा